

बारवहां वार्षिक दीक्षान्त समारोह

जनवरी १२, २०१७

दीक्षान्त प्रवचन



डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड

उपमहानिर्देशक, कृषि शिक्षा
आईसीएआर, नई दिल्ली



जूनागढ कृषि विश्वविद्यालय
जूनागढ - ३६२ ००१
गुजरात

बारहवें दीक्षान्त समारोह के उपलक्ष्य पर
माननीय डॉ नरेन्द्र सिंह राठौड़,
उपमहानिदेशक कृषि शिक्षा, आईसीएआर की ओर से उद्बोधन

आज के समारोह के अध्यक्ष एवं गुजरात के माननीय राज्यपाल एवं जूनागढ कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आदरणीय श्री ओम प्रकाश कोहलीजी, गुजरात सरकार में कृषि एवं उर्जा मंत्री श्री चीमनभाई सापरीयाजी, कुलपति डॉ. ए. आर. पाठकजी, कुलसचिव डॉ. ए. एम. पारखीया, गुजरात के अन्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध सदस्यों, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, प्रिय छात्रों, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं देवियों और सज्जनों ।

जूनागढ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ के बारहवें दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मे माननीय राज्यपालश्री और कुलपति का आभारी हूं । मैं छात्रों को और अनेक माता-पिता को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ और संकाय सदस्यों को विद्यार्थियों के निरंतर मार्गदर्शन एवं शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल एवं मानवीय मूल्यों को प्रदान करने के लिए विशेष सराहना करता हूँ । मैं समस्त छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ की पहली बार भारत सरकार ने कृषि का महत्व समझकर कृषि शिक्षा से संबंधित समस्त विषयों को प्रोफेशनल डीग्री घोषित कर दिया है, अब कृषि छात्र इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं ।

आज निश्चित रूप से मेरे लिये एक यादगार क्षण है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में शिक्षण एवं अनुसंधान में अनुकूल क्षमता का प्रतिनिधित्व करके छात्रों की आजीविका एवं भविष्य का निर्माण करना एवं उनको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज एवं देश की सेवा के लिए सक्षम बनाना, जूनागढ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ की एक बड़ी उपलब्धी है ।

मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अर्ध शुष्क विस्तार में, समुद्री किनारे की क्षारीय जमीन/पानी ओर बरसात की अनियमितता वाले विस्तार में विषम परिस्थितिओ में किसानो के कल्याण के लिये जूनागढ कृषि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट कार्य कर रही है । राष्ट्रीय स्तर पर गेहुं की दस उत्तम

किस्मों में जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जी डब्ल्यू 366 किस्म के ब्रीडर सीड की ज्यादा मांग है। जूनागढ़ मुंगफली और कपास के उत्पादन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मुंगफली के लिये रोग प्रतिकारक और उत्पादन में वृद्धि करने वाली 26 किस्में प्रदान की हैं जिसमें से 8 किस्में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम अरंडी और बाजरा की व्यवसायिक संकर किस्में प्रदान की हैं। कृत्रिम बीजदान द्वारा गीर गाय व जाफराबादी भेंस की प्रचलित नस्लों का संवर्धन कार्य चालु है। जैविक खाद व अन्य जैविक नियंत्रकों के उत्पादन द्वारा जमीन सुधार व पौधों में किट और रोग नियंत्रण के लिये उत्कृष्ट कार्य चल रहा है।

आई.सी.ए.आर. द्वारा ली गयी स्पर्धात्मक परीक्षा द्वारा जे.आर.एफ में 5, एस.आर.एफ में 11 और नेट में 30 विद्यार्थी उत्तिर्ण हुए हैं। इसके अलावा कृषि विस्तार शिक्षा के लिये हाल में छ कृषि विज्ञान केन्द्र खोले हैं। इसी साल नये जिले मोरबी में नये के.वी.के. का शिलान्यास किया गया है, भविष्य में तीन और के.वी.के. शुरू करने की संभावना है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि विश्वविद्यालय में जैविक नियंत्रकों बिबेरीया, ट्राइकोगामा, फेरोमोन ट्रेप, वगैरे का व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया है।

एन. ए. बी. एल. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वस्तरीय फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला में गुजरात के समुद्री किनारे पर रहती मछलीओं की विभिन्न प्रजातीओं की डी. एन. ए. बारकोडिंग की जा रही है, और गीर गाय के गौ मुत्र के गुणधर्मों की जानकारी प्राप्त की है। समुद्री शेवाल द्वारा द्रव खाद तैयार की है, जिससे लोह और जस्ता तत्वों की कमी वाली जमीन को सुधारा जा सकता है।

बी.टी. कपास उसमें आने वाले पिन्क बोल वॉर्म जैसे कीड़े के नियंत्रण के लिये प्रयुक्त तकनीक प्रदान की है। किसानों की मांग के अनुसार सीड विलेज द्वारा बीज उत्पादन में वृद्धि व प्लांटिंग मटीरीयल्स की उपलब्धता कराई जा रही है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास द्वारा सौराष्ट्र विस्तार के केसर आम को जी. आइ. का दरजा प्राप्त हुआ है।

आई.सी.ए.आर, नई दिल्ली मुख्य रूप से कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानव संसाधन विकसित करने की ओर अग्रसित है। कृषि शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आई.सी.ए.आर ने पांचवी डीन कमेटी के प्रस्ताव को पारित कर पाठ्यक्रम में बजारकी मांग के अनुरूप कई उन्नत बदलाव लाये हैं। जिससे विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस बार जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें मुख्य चार टी पर ध्यान दिया गया है। पहले टी का मतलब "ट्रेडिशन" है जिसमें पहले वर्ष में विद्यार्थियों को कृषि के बेसिक्स तथा सिद्धान्त की जानकारी दी जाएगी तथा मूलरूप से भारत में उपलब्ध कृषि की जानकारी दी जाएगी।

दूसरे टी का मतलब "टेकनोलोजी" है इसके अंतर्गत नए पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्षमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाले प्रौद्योगिकी के सही उपयोग के बारे में सिखाया जाएगा।

तीसरे टी का मतलब "टैलेंट" है कि जिसमें विद्यार्थियों की प्रतिभा बढ़ाई जायेगी इसके लिए विद्यार्थियों की नवीनतम एवं रचनात्मक शैली को बढ़ाया जाएगा। चौथे टी का मतलब "ट्रेड" या उद्यमिता के गुण विकसित कर रोजगार प्राप्त करना है, इसमें अन्तिम वर्ष में छात्रों से यही आशा की जाएगी कि वे किस तरह से सफल उद्यमी बनकर रोजगार के विभिन्न आयामों की खोज करें। पांचवी डीन कमेटी ने नई पाठ्यक्रम अन्तर्गत यह कोशिश करी है कि किस प्रकार ज्ञान, कौशल, योग्यता एवं अनुभव का समावेश किया जाये।

कृषि शिक्षा में छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है जिसके लिए आई.सी.ए.आर ने तय किया कि हर कृषि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास जरूरी हों। साथ ही उनके लिए स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जाये जिससे आधुनिक ज्ञान भी दिया जा सके। इसके लिए प्रत्येक क्लासरूम में ईलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगवाए गए हैं जिस पर लाइव वीडियो एवं अन्य जानकारियां विद्यार्थियों को दी जाती है। उसके अलावा पेपरलेस वर्क पर हमारा ध्यान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर आदि का उपयोग किसानों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में हम किसानों को जागरूक

करते हैं कि वे जैविक खेती को अपनाएं जिससे कि पैदावार में कमी न आए और लोगों को उत्तम व शुद्ध खाधान्न प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से लोग आईआईटी में पढाई करना चाहते हैं उसी तरीके से छात्र-छात्राएँ कृषि क्षेत्र में भी रुझान बढाएं।

कृषि को एक आकर्षक एवं प्रख्यात पेशा बनाने में युवा स्नातकों एवं ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालय "स्टूडेंट रेडी" कार्यक्रम लागू कर एवं उद्यमशीलता को बढावा देने के लिए कौशल विकास का महत्वपूर्ण केन्द्र बनें।

कौशल उन्मुख और प्रायोगिक पाठ्यक्रम ग्रामीण युवाओं, खेतहर मजदूर एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व कृषि आधारित आय विकसित करने में आवश्यक सहयोग करेगा।

युवाओं को स्वउद्यम विकास के लिए प्रेरित करने के लिए स्नातक कार्यक्रम के अंतिम वर्षमें एक वर्ष का ग्रामीण उद्यमी जागरूकता विकास योजना (STUDENT READY) कार्यक्रम शामिल किया गया है, जिसके पांच प्रमुख घटक हैं - अनुभवात्मक प्रशिक्षण, ग्रामीण जागरूकता, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास एवं स्टूडेन्ट प्रोजेक्ट हैं। इससे छात्र उच्च शिक्षा लेने के साथ - साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए एवं स्वउद्यम के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जूनागढ कृषि विश्वविद्यालय ने पांचवी डीन कमेटी की रिपोर्ट लागु कर स्टूडेन्ट रेडी कार्यक्रम को चालू कर विद्यार्थियों को "जोब सीकर" की जगह शॉब "प्रोवाइडर" बनाया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अंतिमवर्ष में पूरे साल के लिए इन पाँच विभिन्न घटकों में विभिन्न संकाय के अनुसार कम से कम दो या दो से अधिक घटकों को लागू करके छह महीने के लिए रू. 3000 प्रतिमाह की दर से प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ती प्रदान कर सकते हैं। स्टूडेन्ट रेडी कार्यक्रम में प्रमुख अनुभवात्मक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आई.सी.ए.आर. ने पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 416 ऐसे केन्द्र स्थापित करे हैं। इस स्टूडन्ट रेडी प्रोग्राम से हमारा कृषि का स्नातक पूर्ण ज्ञान ले सके ऐसा हमारा प्रयत्न है। मुझे विश्वास है कि इससे

बहुत बड़ा बदलाव आएगा।

मुझे बहुत खुशी है कि आई.सी.ए.आर. ने राष्ट्रीय प्रतिभा स्कॉलरशिप (National Talent Scholarship) के तहत वर्ष 2016 से अंडर ग्रेजुएट छात्रों की स्कॉलरशिप को रू. 1000/- से बढ़ाकर रू. 2000 /- प्रतिमाह किया गया तथा नई पहल करते हुए वर्ष 2016 से पीजी छात्रों (जो गृह राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं) के लिए स्कॉलरशिप रू. 3000/- प्रतिमाह किया गया। जबकि इन्हें पहले कोई स्कॉलरशिप /वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी। वर्ष 2007 से 2013 तक वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों में अनुभवात्मक लर्निंग इकाइयों की संख्या 264 थी जबकि वर्ष 2014 से 2016, दो वर्षों के दौरान 416 की गयी है जो कि 58 प्रतिशत की वृद्धि है। पिछले दो वर्षों (2014-15 एवं 2015-16) के शिक्षा बजट में भी 50% की वृद्धि हुई है। कृषि शिक्षा के विकास को देखते हुए एक सेन्ट्रल ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटी और 14 नये कोलेज खोले गए हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में एमेरिटस वैज्ञानिक एवं एमेरिटस प्रोफेसर की संख्या बढ़ा कर 100 कर दी गई है। उनकी पारिश्रमिक राशि रू. 25000/- से बढ़ाकर रू. 50,000/- प्रतिमाह कर दी गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी श्री नरेन्द्र मोदीजी के सपनों को साकार करने एवं ग्रामीण भारत के समग्र विकास एवं भारतीय युवाओं की प्रतिभा को उभारने हेतु उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत एक नई योजना "पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना" आरम्भ की है। इस योजना का शुभारम्भ हमारे माननीय कृषि मन्त्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने 25 सितम्बर, 2016 को पं. दीन दयाल उपाध्याय धाम मथुरा, उत्तर प्रदेश में किया। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और कृषि एवं अन्य कृषि संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ग्रामीण विकास के बिना भारत सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और न ही विश्व में अपना स्थान बना सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न पहलों द्वारा ज्ञान की नींव का निर्माण करना है। इस संदर्भ में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय को स्मरण करना

उचित है, जिन्होंने खाद्यान्न में आत्म निर्भरता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्थानीय समुदायों के आर्थिक सम्पन्नता को प्रशस्त करने के लिए आत्म निर्भरता के आधार पर एक मॉडल बनाया। यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि शिक्षा प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि जैविक खेती और टिकाऊ कृषि के प्रति राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार ग्रामीण स्तर पर प्रासंगिक कुशल मानव संसाधन का निर्माण करना, ग्रामीण भारत को प्राकृतिक खेती/जैविक खेती/ग्रामीण अर्थव्यवस्था/टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक समर्थन प्रदान करना तथा इन स्थापित केन्द्रों के माध्यम से ग्राम स्तर उन्नत भारत अभियान की अन्य गतिविधियों का विस्तार करना।

पिछले दो वर्षके दौरान राज्यों को 12 गुना अधिक अर्थात् रूपए 453.85 करोड मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा हेल्थ कार्ड के लिए स्वीकृत किए गए हैं, तथा इस दौरान मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में भी 12 गुना वृद्धि हुई है जिससे 10 हजार तकनीशियों के लिए रोजगार सृजन हुआ है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 51 प्रतिशत वृद्धि के साथ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को माइक्रो इरिगेशन के तहत 2340 करोड रूपए आवंटित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों 2016-17 के लिए 12,517 करोड रूपए की राशि के साथ 23 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना पूरी की जाएगी। इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से लगभग रु. 20 हजार करोड का सिंचाई फण्ड सृजित करने का फैसला किया गया है एवं मनरेगा के तहत वित्त पोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना एन.ए.एम का अनुमोदन 01 जुलाई 2015 को रु. 200 करोड के आवंटन के साथ किया गया जिसके अन्तर्गत 3 वर्षों की अवधि में 585 नियमित थोक मंडियों को एक ई - प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना है। 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 365 प्रस्तावित मंडियों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर इत्यादि के भुगतान करने के लिए रु. 159 करोड अनुमोदित किए गए हैं। कृषि यांत्रिकीकरण में वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को वितरित की गई कृषि मशीनरी संख्या में 57 प्रतिशत की

वृद्धि की गई ।

पहली बार वर्तमान सरकार ने किसानों की मदद के लिए "मोबाइल एप" की सेवाओं का शुभारंभ किया गया है जिनमें फसल बीमा एप एवं एग्रीमार्केट एप मुख्य है। इसी के इन्तर्गत में मार्च 2016 में कृषि उन्नति मेले के दौरान किसान सुविधा एवं पूसा कृषि एप्स का शुभारंभ किया गया। ये "मोबाइल एप्स" किसानों को पूसा द्वारा विकसित प्रवीन तकनीकियों, मौसम, फसल बीमा और बाजार कीमतों आदि के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ किसानों के ज्ञान सशक्तिकरण हेतु "24 घंटे डीडी किसान चैनल" का शुभारंभ किया गया है।

पिछले वर्ष विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 2.5 लाख किसानों को "मृदा हेल्थ कार्ड" का वितरण किया गया साथ ही सार्वजनिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ "किसान - वैज्ञानिक इन्टरफेस" की 604 बैठकों का कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्रों को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए जोनल परियोजना निदेशालयों को कृषि प्रौद्योगिकी अपुप्रयोगों व अनुसंधान संस्थान (अटारी) के रूप में विकसित किया गया। इनकी संख्या भी 8 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है।

कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन द्वारा कृषि उत्पाद का यथोचित मूल्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि गतिशील बाजार व्यवस्था का सटीक अध्ययन एवं उसके नेटवर्क की जानकारी प्राप्त की जाए।

मुझे आशा है कि तेज गति से कृषि के मशीनीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य वृद्धि, शीत भंडारगृहों की श्रंखला, बाजार व्यवस्था में सुधार तथा बाजार भाव के उतार चढ़ाव की जानकारी किसानों तक इंटरनेट आदि के माध्यम से पहुंचाना आज कृषि विकास दर में तेजी लाने के लिए जरूरी हो गया है।

इस दौरान कृषि-अभियांत्रिकी, बायो तकनीकी, डेयरी तकनीक, मात्सयकी पर जोर दिया जायेगा। साथ ही बागवानी, उद्यानिकी एवं सेरीकल्चर के लिए बनेगा समसामयिक पाठ्यक्रम नये विषय जैसे बायोटेकनोलोजी, कम्प्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रीशन एवं डायटिक्स और सेरीकल्चर शिक्षा जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं।

कृषि में युवाओं को आकर्षित एवं स्थापित करने के लिए आई.सी.ए.आर ने एक नई स्कीम आर्य (ARYA) का प्रोग्राम 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है जो कि 25 केन्द्रों की मदद से विशेष कार्यक्रमों द्वारा 5 वर्ष में 10000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। आई.सी.ए.आर कृषि शिक्षा को अंतराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है जिसके तहत छात्रवृत्ति एवं विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

अंत में मैं आप सभी पदवी धारकों को आपके सुनहरे भविष्य के लिये शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ। आप इस विश्वविद्यालय के रत्न हैं, आप अपने निष्ठापूर्वक कार्यों द्वारा विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे और इसकी गरीमा बढ़ाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आप सब समग्र, सार्थक, निडर एवं नैतिक मूल्यों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे एवं अपनी उपलब्धियों से देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

जय हिन्द